(c) what are the major causes identified for the growing sickness in the Ahmedabad textile industry; and

(d) what measures have been taken by Government to retrieve the Ahmedabad textile industry from sickness?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir.

(b) 25 Cotton-man-made Fibre Textile Mills are reported to be closed in Ahmedabad as on 31-12-93. 17 mills are closed under section 56 of Companies Act and 8 mills are reported to be temporarily closed due to financial difficulties and power supply. No mill in Ahmedabad has been closed under I.D. Act. number of workers affected due to closure of mills is 54000 approximately.

(c) The main reasons for sickness are competition from powerlooms in the decentralised sector, low productivity of machine and labour, lack of modernisation and excess labour compliment, increase in cost of inputs and excess capacity.

(d) Government have set up Nodal Agency/Board of Industrial and Financial Reconstruction to evolve and manage Rehabilitation package in respect of sick/closed mills.

ऊन विकास बोर्ड का गठन

985. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऊन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था;

(ख) क्या उक्त बोर्ड की कार्यप्रणाली के लिये कोई नियम बनाए गये है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इन नियमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है और कब तक?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) ऊन विकास बोर्ड का गठन 7 जुलाई, 1989 को किया गया था।

(ख) और (ग) इस समय ऊन विकास बोर्ड की कार्य प्रणाली आन्तरिक नियमों के माध्यम से विनियमित की जाती है।

हथकरघा उत्पादों का निर्यात

986. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन:**
श्री एस० के० टी० रामचन्द्रन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान हथकरघा उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और सरकार को इससे कितनी आय अर्जित हुई है;

(ख) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और हथकरघा उद्योग की सुरक्षा के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनाई है;

(ग) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में हथकरघा बुनकरों को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रावधान किया गया है;

(घ) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिये सरकार द्वारा हथकरघा उत्पादों के निर्यात के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार हथकरघा वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधिक वाणिज्यिक संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) वर्ष 1992-93 के दौरान सूती हथकरघा फैब्रिकों और मेड-अप्स के निर्यात 1033.3 करोड़ रुपये मूल्य के हुए जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

(ख) हथहरघा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने तथा उसके संरक्षण के लिये सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम में हथकरघा क्षेत्र में विशेष रूप से उत्पादन करने के लिए कुछ मदों का आरक्षण किया गया है। अन्य मुख्य योजनाओं में बाजार विकास सहायता योजना,

हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना करने की योजना तथा वित्तीय रियायतें शामिल हैं।

(ग) भारत सरकार ने वर्ष 1993-94 के दौरान हथकरघा क्षेत्र का विकास करने के लिए योजना के अन्तर्गत 51.15 करोड़ रुपये तथा गैर-योजना के अन्तर्गत 198.04 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने सूती हथकरघा उत्पादों के संबंध में वर्ष 1993-94 के लिएँ निर्यात लक्ष्य 410.56 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किया है। अप्रैल-जनवरी, 1993-94 की अवधि के दौरान सूती हथकरघा उत्पादों के निर्यात 335.4 मिलियन अमरीकी डालर (अनन्तिम) मूल्य के हुए।

(च) सरकार ने हथकरघा वस्त्र निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना, प्रमुख बाजारों में मेलों में भाग लेना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करवाना उत्पाद विकास तथा उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों कग माध्यम से गुणवत्ता उन्नयन।

उत्तर प्रदेश के बुनकरों को सूती धागे की आपूर्ति

987. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश को प्रति माह सूती धागे की एक निश्चित मात्रा में आपूर्ति करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार के बुनकरों को सूती धागे की उक्त मात्रा उपलब्ध कराने का भी विचार है;

(ग) क्या सूती धागे के रंगों और रसायनों की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप बुनकर केन्द्रीय सहायता मिले बिना इन वस्तुओं को खुले बाजार से खरीदने की स्थिति में नहीं है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य में बुनकरों की स्थिति सुधारने के लिये सहायता जुटाने हेतु कोई कदम उठाए है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के बुनकरों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के बुनकरों को निजी स्त्रोतों के साथ-साथ केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कई राज्य अभिकरणों द्वारा सूत की आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम भी राज्य अभिकरणों के इन प्रयत्नों में योगदान देता है।

(घ) सूती धागे, रंजक व रसायन के मूल्यों में वृद्धि के कारण इस व्यापार में अवश्य ही असर हुआ है लेकिन इनकी बिक्री को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि बुनाई के कार्यकलाप सामान्य रूप से चल रहे हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) हथकरथा विकास के लिए वर्तमान योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त सहायता दी गई है जिनका विवरण इस प्रकार है:—

(लाख रुपये में)

वर्ष	दी गई सहायता
1990-91	4499.84
1991-92	3769.42
1992-93	3617.64

वस्त्रों का उत्पादन, निर्यात और आयात

988. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में वस्त्र उत्पादन की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) देश की कुल वस्त्र आवश्यकता कितनी है और इसका निर्यात किस-किस देश को कितनी मात्रा में किया जाता है; और

(ग) देश में आयात किये जाने वाले वस्त्रों की मात्रा कितनी है एवं इसे किस-किस देश से आयात किया जाता है और उसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) वर्ष 1992-93 के दौरान देश में कपड़े का कुल उत्पादन 25,475 मिलियन वर्ग मीटर (जिसमें खादी शामिल है) था।

(ख) और (ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कपड़े की कुल मात्रा 32,200 मिलियन वर्ग मीटर होने का अनुमान है। वर्ष 1992-93 के दौरान निर्यातित कपड़े